सं० श्रो॰वि॰/पानी॰/21-85/11211--चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की रागे है कि (1) मुख्य अभियन्ता, हरियाणा राज्य बिजनी बोर्ड, चण्डीगढ़ 2 सिविन, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड, चण्डीगढ़ के श्रामिक श्री कृतन जाल तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई श्रीद्योगिक विवाद है;

ग्रीर चूंकि हरियाणा के राज्यभाल विवाद को न्यायनिर्णय हे तु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझने हैं ;

इसलिये, अब, अोग्रोगिक विवाद अधिनियम, 1947 की जारा 10 की उर आरा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्य गल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं03(44)84-3-श्रम, दिनांक 18 अप्रैल, 1985 द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला को विवाद ग्रस्त या उसमें सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिश्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवाद ग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है:—

क्या श्री कृष्ण लाल की सेवाग्रों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं ० म्रो० वि०/हिसार/3-86/11219.--चृंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि (1)-हाज्य परिवहन हरियाणा, चण्डीम (2) जारल मैंनेजर, हरियाणा राज्य परिवहन, हिसार के श्रमिक श्री निहाल सिंह तथा उसके प्रवन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई ग्रीद्योगिक विवाद है;

श्रीर चुंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना बांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शिन्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिस्चना सं० 9641-1-अम/78-32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ पठित सरकारी अधिस्चना की धारा 7 के अधीन गठित अमन्यापालय, रोहतक, की विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायिनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेत् निर्दिष्ट करते हैं जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा अमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री निहाल सिंह की सेवाग्रों का सुमापन न्यायोचित तथा ठीक हैं? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं श्रो वि०/हिसार/110-85/11226.—चूं कि हरियाणा के राज्यपाल भी रायें है कि (1) परिवहन भ्रायुक्त, हरियाणा राज्य, चण्डीगढ़ (2) जनरल मैंनेजर, हरियाणा राज्य परिवहन, हिसार के श्रीमक श्री लाला राम तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई श्रीद्योगिक विवाद है;

क्रौर चूं कि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को त्यायनिर्णय हेतु निर्द्ध्ट करना बांछनीय समझते है;

इसलिए, अब, अौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शिक्तयों का प्रयोग करने हुवे हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सहकारी अधिसूचना सं० 9641-1-श्रम-78/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ पिटत सरकारी अधिसूचना को धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायाल 1, रोहत क, को विवाद प्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित भी वे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा अमिक के बीच या तो विवाद प्रम्त, मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री लाला राम की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं श्रो वि०/24-86/हिसार/11233 — चूंकि हिरयाणा के राज्यपाल की राये है कि (1) जसवन्त राय चुडामणी ट्रस्ट, मेरठ (2) श्रीमित कमला गुप्ता सचिव, जसवन्त राय ट्रस्ट मेरठ, सुशीला देवी जसवन्त राय मैट० हस्पताल, मेरठ (3) चुडा मणी वैष्णों देवी हस्पताल, हिसार के श्रीमिक श्री मित एस०एल० पाल तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई श्रीद्योगिक विवाद है;

म्रौर चृंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को त्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई मिलतयों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिस्चना सं० 9641-1-श्रम/78-32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ पिठत सरकारी अधिस्चना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवाद प्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायिन गय एवं पंचाट ती र मास में देते हेत् निर्देश्य करने हैं जो कि उनत प्रवन्यकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवाद प्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :--

क्या श्री मित एस०एल० पाल की सेवाग्रों का समापन न्यायोचित तया ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत की हकदार हैं ?

> जे०पी० रतन, उप सचिव, हरियाणा सरकार, श्रम विभाग ।